राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com ) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 21 फरवरी 2026

वर्ष 14,अंक 302, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

महापुरुषों एवं वीरांगनाओं का न हो अपमान सदन में सपा विधायक ने भरी हुंकार...03

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति से की तौबा, कहा- झूठ बोलना पड़ता है....04

# दिल्ली सरकार के एक साल, सीएम रेखा गुप्ता के रिपोर्ट कार्ड में क्या-क्या?

दिल्ली सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. दिल्ली सरकार की तरफ से इसे 'पहला कदम बदलाव का और एक साल विकास का बताया गया. प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि 20 फरवरी 2025 को इसी समय हम सचिवालय पहुंचे थे और अपना कार्यभार संभाला था और पहली कैबिनेट मीटिंग की. ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें एक साल के परिश्रम का जिक्र किया गया है. ये सिर्फ वादों की नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार है।

एक साल के पूरे होने के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है. सरकार ने गरीबों के कल्याण का काम किया. उन्होंने कहा कि सरकार के पहले ही दिन कैबिनेट में आयुष्मान योजना का 10 लाख का कवर दिया. 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया. 30 हजार लोगों ने लाभ उठाया. दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली, जहां 5 रुपए में 70 हजार लोग भोजन पाते हैं।

**13000 फ्लैट को रिनोवेट करवा रहें**

हमारे संकल्प पत्र से लेकर हर काम में दिखेगा कि हमने गरीब झुग्गी वालों के लिए काम किया 700 करोड़ का फंड दिया. ताकि शौचालय, सड़क और जरुरी चीजें बन सके. झुग्गी की जगह मकान देने का काम किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो फ्लैट उन झुग्गी वालों को नहीं दिया। उन 13000 फ्लैट को रिनोवेट करवा रहें हैं और इसे जल्दी ही उनको देंगे। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा

न्यूनतम मजदूरी 22700 रूपए दिल्ली में लागू की जोकि सबसे ज्यादा है. महिला मजदूरों के लिए 500 पालना सेंटर खोले, जहां वो अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती है।

**370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत**

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक साल में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की. लोगों की 70% समस्याओं का समाधान इन्हीं हेल्थ केयर सेंटर पर मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि अस्पतालों पर दवाब घटेगा. इसी साल 1100 तक संख्या ले जाएंगे. इसे अलावा 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक और सेवा शुरू की. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मशीनों की कमी को कम करने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है.जीबी पंजाब अस्पताल में सीटी स्कैनर और कैथ लैब शुरू की. ऐसा पूरा देश में कहीं नहीं है।

पिछली सरकार ने पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार फैलाया था. उसको हटाने के लिए सभी मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटल किया. 100000 लाख आभा आईडी कार्ड बनाए हैं. इससे आने वाले समय में भी लाभ मिलेगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में आयुष सोसाइटी को बनाने का काम भी शुरू किया, पहले नहीं थी. उन्होंने कहा कि अंगदान पर काम किया. दिल्ली में डॉक्टर और स्टाफ की कमी पर काम किया. उन्होंने कहा कि 4000 खाली पदों पर भर्ती निकाली। 1300 नर्सिंग को लेटर दिए. नर्सिंग इंटर्न का भत्ता 500 से 13000 किया।

**7 हजार स्मार्ट क्लास बनाए गए**

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में काम किया. प्राइवेट स्कूलों की फीस के रेगुलेशन के लिए लाया गया. पहले ऐसा कोई कानून नहीं था. 7000 स्मार्ट क्लास और 75 सीएम श्री स्कूलों को बनाने का काम किया. स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी हो. तीन नए करिकुलम शुरू किए।

उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में काम किया. खेल महाकुंभ चल रहा है। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। गोल्ड लाने वालों को 7 करोड़, ब्रोंज को 5 करोड़ और सिल्वर मेडल के लिए 3 करोड़ देंगे। पिछली सरकार में रुकी 44 करोड़ की स्कॉलरशिप दी. दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। सीएम रेखा ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री कहते थे कि दिल्ली को लंदन पैरिस बनाना है. लेकिन हमारी सरकार सोचती है कि दिल्ली को दिल्ली क्यों ना बनाया जाए. दिल्ली में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाए।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर वॉल टू वॉल कारपेंटिंग की जा रही है. 400 किलोमीटर हो गई है। 600 किलोमीटर को भी जल्दी करेंगे। नंदनगरी फ्लाइओवर बनाया। इस साल जुलाई तक बारापुला फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा. पहले की सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया. PWD ने ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया 56000 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान पर काम करना शुरू किया।

**एससी/एसटी बस्तियों में 85 करोड़ की लागत से योजनाएं**

रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने एससी/एसटी बस्तियों में 85 करोड़ की लागत से 146 योजनाओं को शुरू किया. दिल्ली में पानी और सीवर सेवा को ठीक किया. 13 किलोमीटर की सप्लाई पाइप लाइन और 172 किलोमीटर की डिस्ट्रिब्यूशन लाइन को बढ़ाया. 833 पाइप लाइन किलोमीटर के काम जारी किए हैं।

180 किलोमीटर की नई सीवर लाइन डाली. 110 किलोमीटर बदली और 140 किलोमीटर लाइन को शुरू किया जा रहा है. चंद्रावल में पानी सप्लाई के लिए 105 एमजीडी डब्ल्यूटीपी को शुरू कर देंगे. 50 एमजीडी डब्ल्यूटीपी और बन रहा है. वाटर एमनेस्टी स्कीम लाए, जिसमें 352000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए इससे 484 करोड़ मिले. 1400 करोड़ माफ किए. कमर्शियल के लिए भी शुरू कर दिए।

# रमजान में जल्दी छुट्टी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में दी गई छूट

**●बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में जारी आदेश के मुताबिक, रमजान में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को रेगुलर ऑफिस टाइम से एक घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति होगी. यह खास व्यवस्था राज्य में रमजान खत्म होने तक लागू रहेगी।**

रमजान का पाक महीना चल रहा है. कई राज्यों की सरकार की ओर से इस पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समय से पहले छुट्टी करने की इजाजत दी जा रही है. दक्षिणी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी रमजान के दौरान सरकारी और अर्ध-सरकारी ऑफिसों में मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी करने की इजाजत दे दी है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रमजान में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को रेगुलर ऑफिस टाइम से एक घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति होगी. यह खास व्यवस्था राज्य में रमजान खत्म होने तक लागू रहेगी।

**सरकारी आदेश का स्वागत**

सरकार की ओर से जारी आदेश में इस व्यवस्था पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश हर साल मुसलमानों के पवित्र महीने के दौरान रोजा रखने वाले कर्मचारियों को अपने धार्मिक काम करने में आसानी के लिए जारी किए जाते हैं।

सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में राज्य में हर जाति, धर्म, संप्रदाय और समाज की आस्था का सम्मान किया जा रहा है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन का एक शानदार उदाहरण भी है।

**तेलंगाना और आंध्र में भी रियायत**

छत्तीसगढ़ से पहले तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी किया था. इसी तरह का आदेश आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से भी जारी किया गया है, जिसमें मुस्लिम कर्मचारी शाम 4 बजे ऑफिस छोड़ सकेंगे।

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में दुकानों और बिजनेस की जगहों को सुबह 5 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी है. दुकानों और होटलों को हर दिन सेहरी (सुबह का खाना) या सुबह 5 बजे तक काम करने की इजाजत दी गई है।

पवित्र रमजान का महीना कल गुरुवार से शुरू हो गया. देश के कई हिस्सों में परसों बुधवार को रोजे के महीने की शुरुआत का चांद देखा गया और इसके बाद यह पवित्र महीना शुरू हो गया. पवित्र महीने में, रात में मस्जिदों में तरावीह (Taraweeh) नाम की एक खास नमाज पढ़ी जाती है।

## संक्षिप्त ख़बरें

### रिश्तों की मर्यादा तार-तार: अलीगढ़ में गहने और कैश लेकर भांजे के साथ फरार हो गई मामी, 9 लोगों पर केस दर्ज

» पत्नी भांजे विक्रम के साथ जेवर-नकदी लेकर फरार हुई।

» बेटे की सगाई के लिए रखे थे सोने व एक लाख रुपये।

» पुलिस ने नौ लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

**अलीगढ़।** पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भांजे के साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी पत्नी 25 जनवरी 2026 को मायके से लौट रही थी, तभी थाना पालीमुकीमपुर के नागर निवासी उनके भांजे विक्रम उन्हें बहला-फुसलाकर ले गया। पत्नी के पास सोने के आभूषण, एक लाख रुपये नकद और अन्य सामान थे, जो उनके बेटे की सगाई के लिए थे। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि विक्रम ने लूट की नीयत से यह कदम उठाया। जब उन्होंने विक्रम के घर जाकर पूछताछ की, तो विक्रम के परिवार के सदस्यों ने उन्हें धमकाया और कहा कि पत्नी को ले जाने का निर्णय उनके कहने पर लिया गया था।

व्यक्ति ने थाना पालीमुकीमपुर में पत्नी के अपहरण, लूट और धमकी के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने नौ लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक महिला की बरामदगी या आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी रवि चंद्रावाल ने बताया कि महिला की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

# ख़बर का असर: मलिहाबाद-मोहन मार्ग पर निर्माण कार्य में आई तेजी, PWD ने लगाए संकेतक बोर्ड

**● .....मलिहाबाद-मोहान मार्ग: निर्माण की लापरवाही बनी मौत का जाल, रात में गड्ढों में गिर रहे वाहन, शीर्षक से प्रकाशित हुई थी खबर।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**मलिहाबाद।** जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। स्वतंत्र प्रभात द्वारा मलिहाबाद-मोहन मार्ग पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही और संकेतक बोर्डों के अभाव की खबर प्रकाशित किए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) हरकत में आ गया है।

अब विभाग द्वारा निर्माण स्थल पर आवश्यक संकेतक बोर्ड लगाए जा रहे हैं और कार्य को व्यवस्थित ढंग से कराया जा रहा है। पहले जहां बिना सूचना और सुरक्षा इंतजामों के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब चेतावनी बोर्ड और दिशा संकेत लगाए जाने से लोगों को राहत मिली है। मलिहाबाद-मोहन मार्ग का चौड़ीकरण क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इस मार्ग के विस्तारीकरण से यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और स्थानीय व्यापार एवं आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय नागरिकों ने स्वतंत्र प्रभात की सराहना करते हुए कहा कि समाचार के प्रकाशन के बाद विभाग ने त्वरित संज्ञान लिया, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों में सुधार हुआ है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। यह उदाहरण दर्शाता है कि सजग पत्रकारिता और जनहित की आवाज़ मिलकर सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

# पति का आरोप अस्पताल की लापरवाही के कारण पत्नी की हुई मृत्यु

**महेश मिश्रा अपनी पत्नी की मौत के बाद न्याय दिलाने के लिए जगह-जगह लगा रहे है गुहार।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**ब्यूरो प्रयागराज।** प्रयागराज के गोविंदपुर के रहने वाले महेश मिश्रा का है जहां उनकी पत्नी विभा मिश्रा को लूज मोशन हो रहा था जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे उपचार के बाद उनकी मृत्यु हो गई जिसके बाद महेश मिश्रा ने कानूनी मदद न मिलने पर मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी विभा को लूज मोशन हो रहा था वह इलाज कराने निजी अस्पताल पहुँचे। जहां पर उनकी पत्नी का गलत उपचार हुआ उनकी पत्नी के फेफड़ों में इंफेक्शन ।बताया गया और गलत मेडिसिन देने से उनकी इलाज के दौरान सारे शरीर के पार्ट्स काम करना बंद कर दिए इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, महेश मिश्रा जब अपनी पत्नी को दूसरी अस्पताल ले गए इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिससे उनकी मृत्यु हो गई वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में भी पहले अस्पताल के इलाज में गड़बड़ी पाई गई है जिसके बाद उन्होंने जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है मगर अस्पताल पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने अस्पताल को बंद करने की मांग की है जिससे किसी और के परिवार के साथ इस तरह की घटना न घट सके।

### व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजकर करते थे ठगी, आगरा पुलिस ने मध्यप्रदेश से दो ठग किए गिरफ्तार

**आगरा।** थाना साइबर क्राइम आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने और बैंक खातों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मध्यप्रदेश के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी। फाइल इंस्टॉल करते ही मोबाइल का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में चला गया। इसके बाद पीड़ित के बैंक खाते से लगभग 15 लाख रुपये निकाल लिए गए।

**ऐसे करते थे ठगी** जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न बैंकों से जुड़े चेकबुक, एटीएम कार्ड और रजिस्टर्ड सिम हासिल करते थे। इसके बाद 'गोल्डी' नामक व्यक्ति के साथ मिलकर लोगों को फर्जी एपीके फाइल भेजते थे। मोबाइल का एक्सेस मिलते ही खातों से रकम ट्रांसफर कर संदिग्ध खातों में डाल दी जाती थी। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने करीब 70 से 80 बैंक खातों का इस्तेमाल कर 80 से 90 लाख रुपये तक की ठगी की है। ठगी की रकम को विदेशी खातों में भेजकर डॉलर में बदला जाता था और बाद में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाता था।

**गिरफ्तार आरोपी** देवेश यादव (23 वर्ष), मूल निवासी सदर बाजार, थाना कैंट, सागर (मध्य प्रदेश), वर्तमान निवासी गीता कॉलोनी, सागर।

आशीष रजक (22 वर्ष), निवासी ग्राम बालोनिया पिपरा, जिला सागर (मध्य प्रदेश)।

### दुल्हन के ढाई लाख के लहंगे का बदल दिया रंग, अब ब्याज समेत लौटानी पड़ेगी कोलकाता के शोरूम को रकम

**आगरा।** दुल्हन ने शादी के लिए पिंक कलर का लहंगा पसंद किया। कीमत थी ढाई लाख रुपये। शोरूम ने डिलीवरी के दौरान लहंगे का रंग बदल दिया। दुल्हन के स्वजन ने शिकायत की तो शोरूम ने लहंगे को वापस मंगाने के बाद रकम भी नहीं लौटाई तो मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में पहुंच गया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने लहंगे का मूल्य ढाई लाख रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत वादनी को दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में विपक्षी से 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिए। थाना छता के जीवनी मंडी निवासी रितुल जैन पत्नी सुशांत जैन ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में छह अगस्त 2024 को मुकदमा दायर किया था। जिसमें अनुश्री जैन प्रोपराइटर तुष्यम साड़ी शोरूम कोलकाता के अलावा तीन कोस्यिर कंपनी को पक्षकार बनाया था।

# चार दिन से रोडवेज सेवा ठप होने से यात्री परेशान, 100 गांवों की आबादी प्रभावित

**● महोली-उमरिया रोडवेज बस सेवा चार दिन से बंद।**

**करीब 100 गांवों के लोग आवागमन से प्रभावित।**

**बस खराब, जल्द दूसरी बस चलेगी: अधिकारी।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**महोली (सीतापुर)।** कस्बे से होते हुए बड़ागांव, ढकिया, निमचेना और उमरिया क्षेत्र को जाने वाली रोडवेज बस पिछले चार दिनों से बंद है। इससे करीब 100 गांवों की आबादी प्रभावित हो रही है। यह बस रात के समय सीतापुर से महोली के लिए चलती थी और महोली से बड़ागांव होते हुए उमरिया तक यात्रियों को पहुंचाती थी।

ग्रामीणों के अनुसार, यह क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन थी, जिससे आम जनमानस को काफी सुविधा मिलती थी। वर्तमान में बस सेवा पूरी तरह ठप होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड अधिकारियों की लापरवाही के कारण आए दिन सेवा प्रभावित रहती है।

**कई बार की शिकायत**

कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और आने-जाने का यही एकमात्र साधन होने के कारण अभिभावक और छात्र खासे परेशान हैं। उमरिया निवासी संजय, अमित, बलाराम, राहुल और विकास वर्मा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक वर्ष से बस सेवा अनियमित चल रही है। करीब 20 वर्षों से संचालित यह बस क्षेत्र के यातायात की जीवनरेखा मानी जाती है। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि उमरिया की बस खराब हो गई है। वह वर्कशाप में मरम्मत हेतु भेजी गई है। इस रूट पर दूसरी बस संचालित की जाएगी।

# 50 साल बाद घुमंतुओं के बहुरेंगे दिन, रायपुरगंज में 130 परिवारों के लिए बनेगी टाउनशिप

**लहरपुर में 130 घुमंतू परिवारों को 50 साल बाद मिला घर।**

**रायपुरगंज में 11 बीघा जमीन पर टाउनशिप बनाकर बसाया गया।**

**बच्चों को शिक्षा, बड़ों को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लहरपुर,(सीतापुर)।** मुहल्ला ठठेरी टोला में फायर स्टेशन के जमीन पर रह रहे मंगता घुमंतू समाज के 130 परिवारों को 50 वर्ष बाद ही सही, लेकिन दिन बहुरने के आसार हैं। कुछ वर्षों में इस समाज के परिवार के सदस्य भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उन्हें झोपड़ी, पन्नी के नीचे जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। इनको भी पक्की छत सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा बच्चों को बेहतर शिक्षा व परिवार के मुखिया को भीख मांगने के बजाए रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए जिला व तहसील प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

जिलाधिकारी राजा गणपति आर के निर्देश पर मंगता घुमंतू समाज के 130 परिवार को ग्राम रापुरगंज में बसाने को लेकर बीते एक माह से तेजी से कार्य चल रहा है। बीते सप्ताह उनको यहां स्थानांतरित भी कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्तर से मंजूरी मिलने के बाद कार्य और भी ज्यादा अच्छे से गतिमान हो सकेगा।

**परिवारों को निर्धारित स्थल पर गया पहुंचाया**

पचास वर्षों से मुहल्ला ठठेरी टोला में फायर स्टेशन के जमीन पर रह रहे मंगता घुमंतू समाज के लोगों को बसाने के लिए डीएम के निर्देश पर एसडीएम आकांक्षा गौतम एवं तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने ग्राम रायपुरगंज के गाटा संख्या 282 के रकबा .866 हेक्टेअर लगभग 11 बीघे जमीन आवंटित की है। निर्धारित स्थल पर बीते सप्ताह 130 परिवारों को मोहल्ला ठठेरी टोला से ग्राम रायपुर गंज में प्रस्तावित टाउनशिप में बसा दिया गया है। इस दौरान सभी को भोजन पैकेट 200 तिरपाल एवं 150 कंबल भी दिए थे। इसके अलावा घरेलू सामग्री को स्थानांतरित करने में वाहन की भी सुविधा दी थी। तहसील प्रशासन ने जनसहयोग से अभी तक भूमि की मिट्टी पटाई, चहारदीवारी के लिए सीमेंटेड पिलर एवं बिजली ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाइन खिंचवाने के साथ चार सरकारी हैंडपंप भी लगवाए हैं।

**सुरक्षा तो किसी को चाहिए रोजगार**

ज्ञानवती बताती है हम लोग अभी तक कस्बे में रहते थे। अब हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे है। यदि पुलिस की ड्यूटी लग जाए तो

हम लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। हकीम कहते हैं हम लोग अभी तक भिक्षा मांग कर अपने अपने परिवार का जीवन यापन करते है।यदि कोई रोजगार हो जाए तो हम लोगों को अपने बच्चों के जीवनयापन आसान हो जाएगा।

**बच्चों को शिक्षा, बड़ों को मिलेगा रोजगार**

एसडीएम आकांक्षा गौतम ने बताया यहां बसने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने व मुखिया के रोजगार का भी काम किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक केवल 130 परिवारों में एक आकाश नाम का छात्र है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। वह अगले वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा देगा। शेष बच्चे भी शिक्षित हों इसका भी प्रबंध किया जा रहा है। रोजगार के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है।

# रोबोडॉग विवाद - तकनीक, पारदर्शिता और प्रतिष्ठा का टकराव

तकनीकी उपलब्धियों के इस युग में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भविष्य की दिशा तय करने वाली शक्ति माना जा रहा हैए तब सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुत किए जाने वाले दावों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सामने आया रोबोडॉग विवाद इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि तकनीक केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं हैए बल्कि यह भरोसेए प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से भी जुड़ी होती है। इस घटना ने कुछ ही दिनों में अकादमिक जगतए सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श में ऐसी हलचल पैदा कर दी जिसने स्वदेशी नवाचारए संस्थागत नैतिकता और वैज्ञानिक संचार की प्रकृति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

समिट का उद्देश्य देश की उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता को प्रदर्शित करना और शोध संस्थानोंए उद्योगों तथा नीति.निर्माताओं को एक साझा मंच देना था। इसी मंच पर एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रोबोटिक डॉग को आरंभ में तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया गया। प्रदर्शन के दौरान रोबोट की गतिशीलताए संतुलनए निगरानी क्षमता और मनोरंजक क्रियाएँ दर्शकों को आकर्षित कर रही थीं। एक साक्षात्कार में इसे संस्थान की एआई पहलों से जोड़कर प्रस्तुत किया गयाए जिससे आम दर्शकों के बीच यह धारणा बनी कि यह स्वदेशी प्रयास का परिणाम है। लेकिन डिजिटल युग में सूचना की जांच.पड़ताल बहुत तेज़ी से होती है। वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद तकनीकी समुदाय के कुछ लोगों ने इसकी पहचान एक विदेशी व्यावसायिक मॉडल के रूप में कर लीए जिसके बाद आलोचना का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया ने इस विवाद को असाधारण गति प्रदान की। कुछ ही घंटों में यह विषय मीम्सए टिप्पणियों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन गया। इस प्रतिक्रिया में तकनीकी जागरूकता और भावनात्मक राष्ट्रवाद दोनों का मिश्रण दिखाई दिया। कई लोगों ने इसे स्वदेशी तकनीक के नाम पर भ्रम फैलाने का उदाहरण बतायाए जबकि कुछ ने इसे महज़ संचार की त्रुटि या अतिशयोक्ति मानकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। डिजिटल प्लेटफॉर्म की यही विशेषता है कि वह किसी घटना को तथ्यात्मक चर्चा से अधिक प्रतीकात्मक अर्थ दे देता है। रोबोडॉग का मामला भी केवल एक उपकरण का प्रश्न नहीं रह गयाए बल्कि यह देश की तकनीकी छवि और आत्मनिर्भरता की अवधारणा से जुड़ गया।

विवाद बढ़ने पर आयोजकों और संबंधित मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आधिकारिक संकेतों में स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शित जानकारी का सत्यापन आवश्यक है और गलतफ़्हमी पैदा करने वाली प्रस्तुति स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद संस्थान को अपना स्टॉल हटाने का निर्देश दिया गयाए जिसने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया। यह कार्रवाई एक प्रकार से संदेश थी कि तकनीकी प्रदर्शन केवल प्रचार का साधन नहीं हो सकताय उसमें प्रमाणिकता का मानक अनिवार्य है। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप को कुछ लोगों ने कठोर मानाए परन्तु इसे समिट की विश्वसनीयता बनाए रखने के कदम के रूप में भी देखा गया।

संस्थान की ओर से बाद में सफ़ाई दी गई कि उपकरण उनके द्वारा विकसित नहीं किया गया थाए बल्कि छात्रों को वैश्विक तकनीक से परिचित कराने और प्रोग्रामिंग कौशल सिखाने के उद्देश्य से खरीदा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण का दावा नहीं किया गया था और कुछ बयानों की व्याख्या गलत ढंग से हो गई। साथ ही भ्रम के लिए खेद व्यक्त किया गया। यह पक्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक विज्ञान संचार में शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। एक सार्वजनिक प्रस्तुति में अस्पष्ट भाषा या उत्साह में किया गया बयान व्यापक गलतफ़्हमी को जन्म दे सकता हैए जिसका परिणाम प्रतिष्ठा पर दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में सामने आता है।

इस घटना का तकनीकी पहलू भी ध्यान देने योग्य है। विदेशी निर्मित रोबोटिक प्लेटफॉर्म का प्रयोग अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए असामान्य नहीं है। विश्व भर में विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाएँ ऐसे उपकरण खरीदकर उन पर प्रयोग करते हैंए कोड विकसित करते हैं और नई क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। ज्ञान का आदान.प्रदान विज्ञान की मूल प्रकृति है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रस्तुति और वास्तविकता के बीच दूरी बन जाती है। यही दूरी आलोचना का कारण बनी। इस विवाद ने यह भी स्पष्ट किया कि आयातित तकनीक पर काम करना और उसे स्वयं विकसित बताना दो भिन्न बातें हैंए जिनके बीच पारदर्शिता आवश्यक है।

रोबोडॉग विवाद ने एक और महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया आत्मनिर्भरता की अवधारणा को लेकर। स्वदेशी नवाचार का लक्ष्य केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित नहीं होताय उसमें शोध क्षमताए कौशल विकास और वैश्विक तकनीक की समझ भी शामिल होती है। यदि छात्र विदेशी उपकरण पर काम कर रहे हैंए तो यह भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। किंतु जब इसे सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया जाता हैए तो अपेक्षा की जाती है कि उसका संदर्भ स्पष्ट हो। इस घटना ने यह दिखाया कि राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्यों के साथ छोटे संचार दोष भी प्रतीकात्मक रूप से बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं।

सामाजिक स्तर पर यह प्रकरण डिजिटल युग के नैतिक आयामों को भी सामने लाता है। आलोचना लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा हैए परन्तु त्वरित ट्रोलिंग और उपहास कभी.कभी तथ्यात्मक विमर्श को पीछे छोड़ देते हैं। रोबोडॉग के संदर्भ में भी कुछ प्रतिक्रियाएँ व्यंग्य और उपहास से भरी थींए जबकि कुछ ने इसे सुधार और सीखने का अवसर बताया। यह अंतर दर्शाता है कि तकनीकी विषयों पर सार्वजनिक संवाद अभी भी संतुलन तलाश रहा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आलोचना और अपमान के बीच एक महीन रेखा होती हैए जिसे पार करने पर संवाद की गुणवत्ता घट जाती है।

इस घटना का एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया। इसने संस्थानों को यह याद दिलाया कि तकनीकी प्रदर्शन में सत्यापनए दस्तावेज़ीकरण और स्पष्टता आवश्यक है। साथ ही छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह उदाहरण बना कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं हैय उसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत हर उपलब्धि समाज के विश्वास से जुड़ती हैए और वही विश्वास भविष्य की नीतियोंए निवेश और सहयोग को प्रभावित करता है।

अंततः रोबोडॉग विवाद को केवल एक नकारात्मक घटना के रूप में देखना अधूरा दृष्टिकोण होगा। इसे एक ऐसे क्षण के रूप में देखा जा सकता है जिसने देश में तकनीकी विमर्श को अधिक गंभीर और आत्मविश्लेषी बनाया। इसने यह याद दिलाया कि प्रगति का मार्ग केवल उपलब्धियों से नहींए बल्कि उनसे उत्पन्न विवादों और उनसे सीखे गए पाठों से भी बनता है। पारदर्शिताए संवाद और जिम्मेदारी यदि वैज्ञानिक संस्कृति का हिस्सा बनेंए तो ऐसी घटनाएँ भविष्य में बेहतर मानकों की स्थापना का कारण बन सकती हैं। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है तकनीक का विकास केवल मशीनों का विकास नहींए बल्कि विश्वास और उत्तरदायित्व का विकास भी है।

**महेन्द्र तिवारी**

# भारत के लिए बड़ा सबक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद

20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 के लगभग वैश्विक एआई अग्रणी भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी तरह के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहा भारत, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है जब एआई पर इस स्तर का वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर दावा भी किया है कि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणी, प्रख्यात शोधकर्ता, बहुपक्षीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक एक साथ आएंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे।

राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी के साथ चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने आप में यह बताता नजर आ रहा है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी देश भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

दुनियाभर के दिग्गजों के साथ-साथ इस समिट में भारत के भी कई विश्विद्यालय, कॉलेज और स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो एआई को 5वीं औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हुए यहां तक दावा किया कि, 3 लाख से ज़्यादा छात्रों और रिसर्चर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। देशभर के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्टअप ने समिट में एआई मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जाहिर सी बात है कि इस समिट के जरिए जहां चर्चा भारत के युवाओं की बौद्धिक क्षमता और टैलेंट की होनी चाहिए थी, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली एआई समिट में पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एक प्रोफेसर ने बड़े ही गर्व के साथ चार पैरों वाले इस रोबोडॉग की खासियत भी कैमरे पर बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस प्रतिनिधि के हाव-भाव देखने लायक है।इसका नाम 'ओरियन' बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है। सरकारी चैनल सहित देश के कई मीडिया संस्थानों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जोर-शोर से चलाया और छापा भी। लेकिन चीन की तरफ से बयान आते ही पूरा मामला पलट गया। इसके बाद यह पता लगा कि वास्तव में यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी द्वारा बनाया गया एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है।

विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर यह स्वीकार किया कि यह रोबोडॉग उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए यह भी कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे बनाने का दावा नहीं किया। जबकि उनके प्रोफेसर का वायरल वीडियो ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है।

ऐसे में एक बार फिर से सरकार के विजन, नीति और फंड की व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार प्राइवेट विश्विद्यालय और कॉलेजों के सहारे देश में नई, बड़ी और स्पेशल रिसर्च नहीं करवा सकती क्योंकि इनकी भूमिका और इनके कामकाज का पूरा ढांचा ही संदिग्ध है। एडमिशन से लेकर क्लास और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी कई बार गहरे सवाल खड़े हो चुके हैं। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट फाइल करने के नाम पर निजी विभविद्यालयों को जो मोटा फंड देती है, उसकी न्यायिक जांच करवाने का भी समय आ गया है। दरअसल, यह बिल्कुल सही समय आ गया है कि सरकार पहले की तरह सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्विद्यालयों में शिक्षा हासिल कर रही प्रतिभाओं को हर तरह से उभारने में मदद करें। इन संस्थानों में फीस और लालफीताशाही दोनों कम होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और करप्शन पर हर हाल में लगाम होनी चाहिए।

# विकास का विराट विजन : समृद्ध गुजरात की ओर निर्णायक कदम

**जनकल्याण, औद्योगिक विस्तार और भविष्य की तैयारी का संतुलित एवं दूरदर्शी बजट**

गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर गुजरात की एक स्पष्ट रूपरेखा है। चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस विशाल बजट में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 65 प्रतिशत राशि पूंजीगत एवं विकासात्मक कार्यों पर व्यय करने का निर्णय राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शेष राशि पेंशन, वेतन और ब्याज जैसे आवश्यक दायित्वों पर नियोजित की गई है, जिससे वित्तीय अनुशासन और सामाजिक संतुलन दोनों का समन्वय स्थापित होता है। यह बजट दूरदर्शिता, समावेशिता और संतुलित प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सरकार ने ज्ञान( द्द4ड्डठ्ठ)के सूत्र के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति को केंद्र में रखकर योजनाओं का निर्माण किया है। गरीब परिवारों के लिए तीन लाख से अधिक आवासों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि को बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये करना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय केवल घर बनाने का नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास है।

राज्य की 36 प्रतिशत युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति के लिए 4,827 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समरस कुमार और कन्या छात्रालयों के निर्माण से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। लगातार दूसरे वर्ष शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार भविष्य की नींव मजबूत कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में संरचनात्मक सुधार, नई कॉलेजों की स्थापना, खेल सुविधाओं का विस्तार तथा स्वावलंबन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की गई है।

किसानों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त आवंटन, किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज राहत और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएगी। सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगी। यह बजट स्पष्ट करता है कि सरकार किसान और ग्रामीण विकास को विकास की धुरी मानती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 'सखी साहस' योजना, कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण और आर्थिक सहायता की व्यवस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी। यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरक कदम है। औद्योगिक विकास इस बजट की प्रमुख विशेषता है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आधुनिक तकनीक से लैस कर स्मार्ट बनाने का निर्णय उद्योगों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। टेक्सटाइल उद्योग के लिए 2,755 करोड़ रुपये का प्रावधान विशेष रूप से सराहनीय है, जिससे सूरत जैसे टेक्सटाइल हब को नई गति मिलेगी। एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना के अंतर्गत व्यापक सहायता से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना से वैश्विक बाजार में राज्य की उपस्थिति और सशक्त होगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2026 को पर्यटन वर्ष घोषित करना अत्यंत दूरदर्शी निर्णय है। सोमनाथ मंदिर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की पहल, साथ ही अंबाजी मंदिर, गिरनार पर्वत और लोथल जैसे स्थलों के विकास की योजनाएं सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक शक्ति में बदलने का प्रयास हैं। इससे स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिलेगा। शहरी विकास में 17 प्रतिशत की वृद्धि कर नगरपालिकाओं और महानगरों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है। पांच नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा संतुलित शहरीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। स्मार्ट पार्किंग, दैनिक जलापूर्ति और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शहरों को आधुनिक स्वरूप देगा। सूरत मेट्रो लाइन-2 के विस्तार के लिए आवंटित राशि से शहर को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इससे मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को समय व लागत की बचत होगी।

खेलकूद का बजट 155 प्रतिशत तक बढ़ाना राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को दर्शाता है। अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी बनाने का संकल्प और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय खेल परिसरों के निर्माण का प्रावधान युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। यदि भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे वैश्विक आयोजन गुजरात में होते हैं, तो राज्य की वैश्विक पहचान और सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी व्यापक निवेश किया गया है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के विकास, सिविल अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। यह सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करता है।

राज्य की वित्तीय स्थिति भी संतुलित और अनुशासित दिखाई देती है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के नियंत्रित स्तर पर है और सार्वजनिक ऋण अनुपात में कमी दर्शाती है कि सरकार विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए हुए है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का संकेत है।

कुल मिलाकर यह बजट केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि भविष्य के गुजरात की नींव रखता है। गरीबों के लिए आवास, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार, किसानों के लिए राहत, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और शहरों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा इन सभी पहलुओं को समेटे यह बजट विकास का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा रोडमैप है, जो गुजरात को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। जनता को विश्वास है कि यह सपना शीघ्र ही साकार होगा और गुजरात प्रगति की नई इबारत लिखेगा।

**कांतिलाल मांडोत**

# संपादकीय

## संवेदनशील प्रशासन और संयमित छात्रः संतुलन ही समाधान

[ दूसरी पालियों में समाधान, पहली में जीवन की हार ]

[ परीक्षा से बड़ी है जिंदगी, अंक केवल संकेत हैं, मूल्य नहीं ]

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया—और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की नंगी सच्चाई है—जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ करुणा चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरते हैं। दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था—जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों की धड़कन सुनाई ही नहीं देती?

इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रतियाँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली—और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही विरोधाभास सबसे चुभता है—जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लचीलापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों? क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या करुणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है? पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष भी आता है। पर यदि जीवन का पन्ना ही फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम फिर नहीं जोड़ सकता। क्षणिक आवेग में उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन घाव बन जाता है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है।

हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का प्रमाणपत्र बन गए हैं। माता-पिता की आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चकाचौंध—ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है। ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाती है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं।

प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक खिड़की खुली रहनी चाहिए—ऐसी व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी त्रुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए। छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की रीढ़ है; अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा के दिन तैयारी केवल पाठ्यक्रम की नहीं, परिस्थिति की भी होनी चाहिए—समय से पहुँचना, विकल्प सोचकर चलना, जोखिम से बचना। किंतु यदि कभी चूक हो जाए, तो उसे जीवन की हार का नाम न दें। सच्चा साहस गिरकर फिर खड़े होने में है, न कि एक ठोकर को अंतिम सत्य मान लेने में। असफलता से जूझना परिपक्वता है; क्षणिक आवेग में स्वयं को ही दंडित कर देना नहीं। जीवन एक लंबी दौड़ है—एक मोड़ फिसलन भरा हो सकता है, पर वह पूरी मंज़िल को निगल नहीं सकता। यह घटना हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है—संतुलन ही व्यवस्था और जीवन, दोनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नियम हों, पर उनमें मानवता की धड़कन भी हो; अनुशासन हो, पर उसके साथ समझ और संवेदना भी। उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी भी क्षणिक आघात को अंतिम फैसला न बनने दें। समाधान किसी एक पक्ष की कठोरता में नहीं, दोनों के सामंजस्य में छिपा है। जब प्रशासन विवेकशील हो और युवा संयमित, तभी त्रासदियों के रास्ते बंद होते हैं। यदि व्यवस्था पत्थर न बने और छात्र आवेग के बजाय साहस चुनें, तो अनेक घरों की रोशनी बच सकती है। परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा समय पर बंद हो सकता है, पर जीवन का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए—और उसे खुला रखना ही समाज, सिस्टम और छात्र, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

**प्रो. आरके जैन अरिजीत**

# दिल्ली-पैरिस सपनों की उड़ान

भारत और फ्रांस ने 1947 में ही भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। वर्ष 1998 में शुरू हुई फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत की किसी पश्चिमी देश के साथ पहली और फ्रांस की यूरोपीय संघ से बाहर पहली साझेदारी थी। इस रणनीतिक साझेदारी में दोनों देशों का दृष्टिकोण शामिल रहा जिसके तहत वे मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से अपनी-अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना चाहते थे। रक्षा एवं संरक्षा, नागरिक परमाणु मामले और अंतरिक्ष इस रणनीतिक सहयोग के प्रमुख स्तम्भ रहे। अब इस साझेदारी का विस्तार काफी व्यापक हो चुका है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुम्बई में दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप की और ऊंची उड़ान पर ले जाने का ऐलान किया। दोनों देश अब एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो ग्लोबल आर्डर को बदलने की ताकत रखते हैं। दोनों देशों की दोस्ती अब समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंची उड़ान तक विस्तार पा चुकी है। भारत और फ्रांस में राफेल से लेकर पनडुब्बी निर्माण समेत 21 समझौते हुए हैं। मैक्रों की यह यात्रा केवल आपसी संबंध बढ़ाने तक सीमिति नहीं है।

यह भारत की उस खोज को दर्शाती है जिसे 'बहुध्रुवीय पश्चिम' कहा जा सकता है। यूरोप को अब केवल वाशिंगटन का सहयोगी या अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के मैदान में एक निष्क्रिय खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा जाता है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है जो भारत के आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन में योगदान देने के साथ-साथ दिल्ली के लिए विदेशों में अपनी रणनीति को व्यापक बनाने में सक्षम है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रूस और चीन द्वारा इसे अपनी कूटनीति का मुख्य विषय बनाने से बहुत पहले ही फ्रांस 'बहुध्रुवीय विश्व' के पक्ष में राजनीतिक सक्रियता के शुरुआती समर्थकों में से एक था।

पेरिस ने लगातार यूरोपीय 'रणनीतिक स्वायत्तता' की वकालत भी की है। इस साझा शब्दावली ने दिल्ली और पेरिस के बीच कुछ हद तक सहजता का माहौल बनाया है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का साथ अब तक का सबसे सफल मॉडल रहा है। साझा बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि अब सहयोग सिर्फ खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। अब फोकस को-डिजाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन पर होगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों देशों ने जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन के लिए बड़े स्तर पर हाथ मिलाया है। 26 राफेल-मैरीन फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि के साथ ही अब फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की दिशा में भी बात आगे बढ़ी है।

सैफरन ग्रुप और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए इंजन विकसित करेंगे। इतना ही नहीं, भारत में राफेल विमानों में लगने वाले एम-88 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सुविधा भी स्थापित की जाएगी। टाटा और एयरबस मिलकर 'मेक इन इंडिया' के तहत एच-125 फाइनल असेंबली लाइन शुरू कर चुके हैं। यह प्राइवेट सेक्टर में हेलीकॉप्टर बनाने की भारत की पहली ऐसी सुविधा है। वहीं, स्कॉर्पीन पनडुब्बी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई पनडुब्बियों के निर्माण पर भी सहमति बनी है।

फ्रांस ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में भी अपनी गहरी रुचि दिखाई है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत के हथियार फ्रांस की सेना की भी ताकत बन सकते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर दबाव डालते रहते हैं और पश्चिमी जगत पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इसके बावजूद दिल्ली और पैरिस की साझेदारी अमेरिका के विरोध में न होकर एक अपना नया मार्ग तलाशना है। यह फ्रांस की भू राजनीतिक सोच में परिवर्तन का संकेत देता है। इमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली में चल रहे एआई ग्लोबल समिट में भी भाग लिया। एआई में अभी तक अमेरिका और चीन का वर्चस्व है।

अमेरिका के कार्पोरेट सैक्टर और चीन के सत्ता नियंत्रण के बीच भारत-फ्रांस एक ऐसे एआई ढांचे का विकास चाहते हैं जो संप्रभुता की रक्षा करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करें। भारत के पास यूरोप और अन्य देशों के साथ एआई में काम करने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। यही कारण है कि भारत फ्रांस ने आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस क्षेत्र में समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने एक सुरक्षित और भरोसेमंद एआई बनाने पर जोर दिया है जो मानव के काम आए। आतंकवाद, हिन्द प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर भी फ्रांस और भारत के विचार एक समान हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश नियम आधारित व्यवस्था चाहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि दक्षिणी चीन सागर और हिन्द महासागर में चीन की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। फ्रांस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। मैक्रों ने भारतीय लोगों और छात्रों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा की घोषणा की है। फ्रांस ने 2030 तक 30 हजार भारतीय छात्रों को बुलाने का लक्ष्य रखा है। यह दोस्ती तकनीकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर भारत को ताकतवर बनाने की क्षमता रखती है। भारत राजनीतिक रूप से फ्रांस के साथ एक स्थिर और प्रगतिशील साझेदारी का ?निर्माण कर सकता है। इससे पूरी दुनिया में ग्लोबल आर्डर को नई दिशा मिल सकती है।

**स्वामी-** स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

## संक्षिप्त खबरें

### लालच देकर जमा कराये रुपए,ऑफिस बंद कर फरार हुई कंपनी

**लालगंज (रायबरेली)।** कस्बे के गुरबक्शगंज चौराहे पर संचालित एक कंपनी पर महिलाओं ने ठगी का आरोप लगाया है। बुधवार को दो दर्जन से अधिक महिलाएं कोतवाली पहुंचीं। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की। सातनपुर गांव की रुमन पत्नी रोहित ने बताया कि कंपनी से जुड़ी 50 से अधिक महिलाओं से 17,700 रुपये जमा कराए गए। बदले में हर महीने 3 हजार रुपये देने का झांसा दिया गया। शुरू में भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में कोई पैसा नहीं मिला। अब करीब एक माह से कंपनी का ऑफिस बंद है। वहा काम करने वाले कर्मचारी फरार हो गए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में महिलाओं ने बताया गया कि सातनपुर के अलावा अकोहरी चौराहा, नरी चक, कुंभी, अंबारा पश्चिम, चक मलिक भीटी समेत कई गांवों की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की गई। सभी ने संयुक्त रूप से शिकायत दिया है। रूपा ने कहा कि उसने मनरेगा की मजदूरी से पैसा जोड़ा था। लाभ का लालच देकर रकम जमा कर दिया। शकुन ने बताया कि गहने गिरवी रखकर कंपनी में जुड़ी थी। अब न पैसा है और न ही कंपनी का कुछ पता चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी की महिला कर्मचारी उनके घर आती थीं। विश्वास जीतती थीं। कई बार रात में रुकती भी थीं। इसी भरोसे पर उन्होंने रकम जमा करा दी। अब आफिस बंद कर सब गायब हो गए हैं। सरस्वती, रामपियारी, सिया दुलारी, रमाकांति, बिंदेश्वरी, नीलम, प्रतीक्षा, रीना और अन्य महिलाओं ने भी कार्रवाई की मांग की है।

### मध्य प्रदेश के युवक की लखनऊ में सड़क हादसे में मौत, मोबाइल फोन से हुई पहचान

**मध्य प्रदेश के युवक की सड़क हादसे में मौत।**

**मोबाइल फोन से हुई मृतक की शिनाख्त।**

**पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की।**

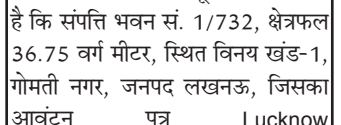


**बंथरा (लखनऊ)।** मध्यप्रदेश के छतरपुर निवासी 32 वर्षीय युवक की बंथरा के कटी बगिया इलाके में गुरुवार की शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल फोन से युवक की शिनाख्त कर सूचना परिवारजन को दी है। शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। बंथरा थाना प्रभारी राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम कटी बगिया में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी। मौके पर पहुंचकर टीम ने छानबीन की तो उसके पास मिले मोबाइल फोन से युवक की शिनाख्त छतरपुर जिले के हिंदौर गांव निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार के रूप में हुई। इंस्पेक्टर के मुताबिक, राजेश अपनी बाइक से बंथरा से कानपुर की ओर जा रहे थे। उनकी बाइक के पिछले हिस्से में लोहे की एक लंबी राड लगी थी। युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना था। पुलिस को आशंका है कि राड में टक्कर लगने से हुई हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को सूचित कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है।

**सूचना**

यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संपत्ति भवन सं. 1/732, क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर, स्थित विनय खंड-1, गोमती नगर, जनपद लखनऊ, जिसका आवंटन पत्र Lucknow Development Authority द्वारा श्री सुरेश कुमार सक्सेना के पक्ष में निर्गत किया गया था, तथा तत्पश्चात Lucknow Development Authority द्वारा श्री सुरेश कुमार सक्सेना के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांक 16/03/1989 एवं श्री सुरेश कुमार सक्सेना द्वारा श्री त्रिलोकी नाथ के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांक 30/12/1993, पुस्तक सं. 1, खण्ड 2284, पृष्ठ 357 से 372, क्रमांक 7590, तथा शुद्धि पत्र/तितम्मा दिनांक 30/04/1994, पुस्तक सं. 1, खण्ड 2445, पृष्ठ 379 से 364, क्रमांक 3135 के मूल अभिलेख खो/गुम हो गए हैं।

उक्त दस्तावेज यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हों अथवा उनके संबंध में कोई जानकारी हो तो अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

**नामः सिद्धार्थ शंकर तिवारी, पुत्र श्री राम नंदन तिवारी**
**पताः ई-3/907, सेक्टर-आई, एल.डी.ए. स्टेडियम, अलीगंज, लखनऊ - 226024**
**संपर्कः 8795362801**

# महापुरुषों एवं वीरांगनाओं का न हो अपमान सदन में सपा विधायक ने भरी हुंकार

- **लखनऊ में जीपीओ के सामने लगी आवंती बाई लोधी की प्रतिमा को लेकर विधायक राहुल लोधी ने कहा हो रहा अपमान !**
- **जनमहोत्सव के दिन लोधी समाज के साथ अन्य समाज नहीं कर पाता माल्यार्पण, सुरक्षा प्रबंधन पर भी उठाएं सवाल !**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**राजेश कुमार**

**रायबरेली-** विधानसभा सत्र के दौरान हरचंदपुर सपा विधायक राहुल लोधी के द्वारा उठाए गए मुद्दे सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सुर्खियों में है राहुल लोधी ने कहा प्रदेश भर में लोधी समाज के महापुरुषों व लोधी समाज के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है व निंदनीय है। वीरांगना रानी आवंती बाई लोधी की प्रतिमा को लेकर समाजवादी पार्टी के हरचंदपुर से विधायक राहुल लोधी ने कहा विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर जीपीओ के ठीक सामने वीरांगना रानी आवंती बाई लोधी की प्रतिमा स्थापित है 16 अगस्त के दिन प्रदेश भर से लोधी समाज के साथ अन्य पिछड़े वा दलित समाज के लोग माल्या अर्पण करना चाहते हैं लेकिन प्रतिमा स्थल के चारों ओर अवैध रूप से होल्डिंग लगाकर पूरी तरीके से प्रतिमा को ढकने का काम किया जाता है जिससे जन भावनाएं संपूर्ण समाज की आहत हो रही है सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा के अगल-बगल इस तरीके के व्यवधान उत्पन्न ना हो सके आपको बता दे समाजवादी पार्टी से विधायक राहुल शिव गणेश लोधी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबियों में से एक माने जाते हैं समाजवादी पार्टी राहुल लोधी के जरिए लोधी समाज में अपनी छाप छोड़ना चाह रही इसके दृष्टिगत संपूर्ण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में राहुल लोधी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं सन 2022 के विधानसभा चुनाव में हरचंदपुर विधानसभा सीट से परचम लहराने वाले राहुल लोधी ने सदन के भीतर जनपद रायबरेली की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं रायबरेली जनपद से जुड़े एक अत्यंत गंभीर विषय पर सरकार से जवाब चाहता हूं रायबरेली में कुछ पूर्व विधायकों को आज भी पुलिस जिप्सी एस्कॉर्ट और सरकारी गनर उपलब्ध कराए गए हैं क्या यह सच है यदि हाँ, तो किस नियम, किस शासनादेश और किस आधार पर यह सुविधा दी गई है जनपद में कुल कितने पूर्व विधायक इस सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं प्रत्येक पर प्रतिमाह

कितना सरकारी धन व्यय हो रहा है जबकि हकीकत यह है कि यह धन जनता की गाढ़ी कमाई से आता है वर्तमान स्थितियां इतनी भयावह है की जब आम नागरिक भाजपा सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहा है और जब वर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे इस दौर में तब पूर्व विधायकों को यह विशेष सुविधा देना क्या न्यायसंगत है उन्होंने उठाए गए सवालों को लेकर सरकार से स्पष्ट उत्तर मांगा अपने विचार स्पष्ट करते हुए राहुल लोधी ने कहा क्या इस सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा कर अनावश्यक सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया जाएगा या फिर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ऐसे ही चलता रहेगा सदन में हरचंदपुर विधानसभा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर राहुल लोधी द्वारा वेबाकी पूर्ण तरीके से क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रादेशिक पटल पर बुलंद किया ।

### ED ने अनी समूह की 7.30 करोड़ रुपये की संपत्तियां की कुर्क, निवेशकों के 110 करोड़ रुपये हड़पने का मामला

**लखनऊ।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों के 110 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में अनी समूह की 7.30 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनी बुलियन ट्रेडर्स एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज मनी लान्ड्रिंग के मामले में तीन अचल और एक चल संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है। इनमें अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, दिल्ली और उत्तरकाशी में स्थित अचल संपत्तियों के अलावा एक फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) भी शामिल है। ईडी ने अजीत कुमार गुप्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआइआर और शिकायतों के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि अजीत कुमार गुप्ता और उसके सहयोगियों ने लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं का लालच देकर करीब 110 करोड़ रुपये की ठगी की थी। निवेशकों से जुटाई गई राशि को अनी समूह की विभिन्न कंपनियों और आइविजन क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। सोसाइटी पर भी अजीत कुमार गुप्ता का नियंत्रण था। ईडी के अनुसार, ठगी से प्राप्त धन का उपयोग अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने में किया गया।

# विद्यार्थियों ने शिवाजी महाराज के जीवन से लिया प्रेरणा संदेश

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**सीतापुर।** आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, सीतापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिवाजी महाराज वीरता, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे।

प्राचार्या डॉ. स्तुति वर्मा ने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया। डीन अकादमिक श्रीमती रुचि सिंह ने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।उपनिदेशक डॉ. आदित्य सिंह, डॉ. अब्दुल रब खान तथा रजिस्ट्रार रोहित सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों को अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा का महत्व समझाया। कार्यक्रम में अध्यापकगण राजीव कुमार, ऋषभ शुक्ल, अनुभा धुरिया, अभिमन्यु, मोहित यादव, रेहान, तान्या, साहिल सिंह तथा स्टाफ सदस्य अरुण सिंह, प्रीति यादव, प्रवीण यादव, प्रीति तिवारी, अबरार अली, तिलक राज, रमा सिंह सहित अन्य कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

# केरला स्टोरी 2 पर काम करना विपुल अमृतलाल शाह के साथ अब तक का सबसे विकसित सहयोग है।

- **द केरला स्टोरी 2 में विपुल शाह के साथ अपनी तीसरी साझेदारी पर बोले सुमित गहलावत।**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

सुमित गहलावत द केरला स्टोरी 2 में अपने अब तक के सबसे परतदार किरदारों में से एक निभाते नजर आएंगे और इस भूमिका के लिए उन्होंने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में रिलीज़ हुए ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के साथ फिर से काम करते हुए सुमित इस अनुभव को बेहद क्रिएटिव और सहयोगात्मक बताते हैं। इससे पहले द केरला स्टोरी और बस्तर में विपुल शाह के साथ काम कर चुके सुमित के लिए यह उनकी तीसरी साझेदारी है, लेकिन उनके मुताबिक यह सबसे ज्यादा विकसित महसूस हुई। सुमित ने कहा, 'जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, तो समझ गया कि यह किरदार बेहद परतदार है। लगभग हर सीन के साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से एक नई गहराई सामने

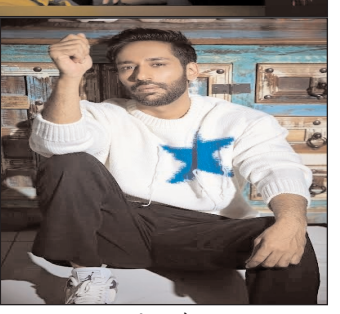

आती है। यही प्रोग्रेशन मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर गया। किरदार के साथ न्याय करने के लिए कलाकारों के 12-13 लंबे प्रेप सेशंस हुए, जिनमें विपुल शाह अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद खुद मौजूद रहे। द केरला स्टोरी 2 में सुमित 'सलीम' का किरदार निभा रहे हैं, जो कहानी में नायक से खलनायक बनने तक का सफर तय करता है। यह किरदार भावनात्मक गहराई और मनोवैज्ञानिक सटीकता दोनों की मांग करता है। सुमित के लिए तैयारी का मतलब था स्क्रिप्ट में पूरी तरह डूब जाना। वह कहते हैं, 'मैं हमेशा मानता हूं कि कैमरे के सामने जाने से पहले स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ना जरूरी है। मैंने इसे 25 से ज्यादा बार पढ़ा होगा। जब किरदार इतना बदलता है, तो हर बारीकी को भीतर तक समझना जरूरी होता है। ' एक मजबूत किरदार, गहन तैयारी और विपुल शाह व कामाख्या नारायण सिंह के सहयोगात्मक विजन के साथ द केरला स्टोरी 2 में सुमित गहलावत का सलीम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि ट्रेलर को पहले ही खूब सराहना मिल रही है।

# गांधी चौराहे पर भीषण जाम, आधे घंटे फंसी रही एंबुलेन्स

- **मरीज़ को लेकर जिला अस्पताल जा रही एंबुलेंस जाम में फंसीं रहीं, यातायात व्यवस्था चौपट**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लालगंज (रायबरेली)।** कस्बे के गांधी चौराहे पर गुरुवार दोपहर अचानक भीषण जाम लग गया। करीब आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। जाम में सरेनी से मरीज लेकर जिला अस्पताल जा रही एंबुलेंस भी फंस गई। देर तक चालक सायरन बजाता रहा लेकिन एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिला। दोपहर करीब 12 बजे वाहनों का दबाव बढ़ गया। गांधी चौराहा में सड़क के दोनों ओर ई-रिक्शा खड़े थे। कुछ वैध पार्किंग में थे तो कई अवैध रूप से सड़क पर खड़े कर सवारियों के इंतजार में थे। इससे रास्ता संकरा हो गया। देखते ही देखते सड़क पर दोनों तरफ लंबी कतारें लग गईं। जाम में एंबुलेंस और स्कूल वाहन फंस गए। इस दौरान एंबुलेंस आगे निकलने की चक्कर में स्कूल वाहन से भिड़ गई। स्कूल बस का साइड मिरर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा नगर की मेंन रोड पर डाकघर कार्यालय से लेकर अस्पताल मोड़ तक वाहनों की लाइन लग गई। स्कूली वाहन भी जाम में फंस गए। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद यातायात को धीरे-धीरे बहाल किया गया। करीब आधे घंटे बाद जाम खुल सका।व्यापारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अप्पू शर्मा, लाला अवस्थी और सानू बाजपेई ने बताया कि दो माह पहले एसडीएम ने मुनादी कराकर सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। लेकिन अब तक अभियान नहीं चला। नई बाजार मोहल्ले में भी सड़क तक दुकानें फैली हुई हैं। इससे रोज जाम की स्थिति बनती है। स्थानीय लोगों ने नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने और ई रिक्शा चालकों के लिए स्थायी पार्किंग व्यवस्था बनाने की मांग की है।

# फिल्म का नाम नहीं होगा 'घूसखोर पंडत', फिल्म निर्माता ने शीर्षक लिया वापस

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**नई दिल्ली, प्रेट्र।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स की आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'घूसखोर पंडत' के विरुद्ध याचिका का निपटारा कर दिया, जब फिल्म निर्माता नीरज पांडेय ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने फिल्म का शीर्षक और सारी प्रचार सामग्री वापस ले ली है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पांडेय का हलफनामा रिकार्ड में लेने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया और उम्मीद जताई कि यह विवाद हर तरह से शांत हो जाएगा। यह याचिका ब्राह्मण समाज आफ इंडिया के राष्ट्रीय आयोजन सचिव अतुल मिश्रा ने दाखिल की थी। अपने हलफनामे में पांडेय ने कहा, 'पहले वाला शीर्षक घूसखोर पंडत पूरी तरह से वापस ले लिया गया है और इसका किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले वाले शीर्षक जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा। ' उन्होंने कहा, 'फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है और अभी संपादन के चरण में है। इस वजह से रिलीज नहीं हुई है।' सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'पंडत शब्द में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन पंडत के साथ घूसखोर शब्द भी था। हमें दूसरे शब्द से दिक्कत है, पहले शब्द से नहीं।'

### रमजान में भी मस्जिदों से नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, यूपी विधान सभा में उठी मांग को संसदीय कार्य मंत्री ने नकारा

**रमजान में लाउडस्पीकर की मांग विधानसभा में उठी।**

**सपा सदस्य कमाल अख्तर ने अनुमति का अनुरोध किया।**

**सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मांग नकारी गई।**

**लखनऊ।** विधान सभा में गुरुवार को रमजान के दौरान रोजा इफ्तार तथा सहरी के वक्त लाउडस्पीकर के माध्यम से उदघोष करने की मांग पर चर्चा हुई। सपा सदस्य कमाल अख्तर ने रोजा इफ्तार व सहरी के समय लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना दिए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नकार दिया गया। विधानमंडल बजट सत्र के नौवें दिन विधान सभा में सपा सदस्य ने कहा कि सरकार त्योहारों के समय लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देती है। रामलीला का उदाहरण दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश रात में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाने की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह परंपरा उस समय की है, जब घड़ियां नहीं होती थीं।

# यूपी विधान सभा में उठा गलगोटिया विश्वविद्यालय का मुद्दा, सपा सदस्य ने कही ये बात

- **गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीनी रोबोट को अपना बताने का आरोप।**
- **सपा सदस्यों ने विधानसभा में जांच और कार्रवाई की मांग की।**
- **मामला शैक्षणिक पारदर्शिता और वैज्ञानिक साख से जुड़ा है।**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लखनऊ।** नई दिल्ली में चल रहे एआइ इंपैक्ट समिट के दौरान चीनी रोबोट को अपना बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला गुरुवार को विधान सभा में भी उठा। सपा सदस्य इंजीनियर सचिन यादव व पंकज मलिक ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जांच कराने व कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि बगैर जांच-पड़ताल के इस उत्पाद को कैसे समिट में शामिल कर लिया गया। यह न केवल शैक्षणिक पारदर्शिता बल्कि देश की वैज्ञानिक साख से भी जुड़ा गंभीर विषय है।

सपा सदस्यों द्वारा इसे उठाने पर पहले विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना कहा कि यह समिट यूपी में नहीं हो रही है और न ही इसे प्रदेश सरकार ने आयोजित कराया है। इसलिए इस पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती है। हालांकि सपा सदस्यों के अनुरोध पर बाद में इसे सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए सपा सदस्यों को अपनी नोटिस पढ़ने की इजाजत दे दी गई।

सचिन ने कहा कि चूंकि विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में संचालित है, इसलिए इसकी जवाबदेही राज्य सरकार के दायरे में आती है। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि संबंधित विश्वविद्यालय का पक्ष सदन के समक्ष रखा जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर आंच न आए। अधिष्ठाता मंजू सिवाच ने सपा की इस नोटिस को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेज दिया है।

# कबाड़ बन चुके रेल इंजन पर युवकों ने बनाई रील, अब रेलवे ने लिया ये एक्शन

- **कबाड़ इंजन पर रील बनाने पर रेलवे ने की कार्रवाई।**
- **युवकों की पहचान के लिए साइबर सेल को भेजा पत्र।**
- **अनाधिकृत प्रवेश, संपत्ति नुकसान पर मुकदमा दर्ज।**

**लखनऊ।** आलमबाग के डीजल शेड में खड़े कबाड़ बन चुके एक इंजन पर इंटरनेट मीडिया के लिए रील बनाने वाले युवकों के खिलाफ रेलवे ने मामला दर्ज किया है। रेलवे ने साइबर सेल को पत्र भेजकर युवकों की इंस्टाग्राम आइडी का पता लगाकर उनकी पहचान करने के लिए पत्र भेजा है। दरअसल बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ। इस वीडियो को कुछ युवकों ने डीजल शेड के सूनसान पड़े हिस्से में खड़े निष्प्रयोज्य डीजल इंजन पर बनाया था। वीडियो में इंजन के लीवर सहित कई हिस्सों में छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया था।

कई लोगों ने इस वीडियो को रेलवे को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर टैग करते हुए सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। आखिरकार रेलवे सुरक्षा बल की डीजल शेड पोस्ट ने अज्ञात युवकों के खिलाफ बिना अनुमति के रेलवे परिसर में प्रवेश और संपत्ति को नुकसान पहुंचने के आरोप में रेलवे एक्ट की धारा 145 और 147 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब आरपीएफ ने साइबर सेल को वीडियो पोस्ट करने वाली आइडी का पता लगाने और अज्ञात युवकों की पहचान में मदद के लिए पत्र भेजा है।

**खतरा बनीं निष्प्रयोज्य कालोनियां**

रेलवे अपनी कई कालोनियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर चुका है। खाली हो चुकीं कई कालोनियां रेल लाइन किनारे हैं। ऐसे में इन कालोनियों से होकर हर अवांछित तत्व रेल लाइन तक आ जाते हैं। चोरी जैसी घटनाएं भी इन कालोनियों के कारण हो रही हैं।

# यूपी में अब रविवार को भी हो सकेगी रजिस्ट्री, समय के साथ हुए कई बदलाव; लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

- **» अवकाश के दिन खुलेगा उपनिबंधक कार्यालय, समय सहित कई बदलाव**
- **» प्रदेश में जिन तहसीलों में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय वहां लागू हुई व्यवस्था**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लखनऊ।** प्रदेश के जिन तहसीलों में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं वहां पर अब रविवार को भी रजिस्ट्रियां हो सकेगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों के रोस्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश के मुताबिक जिस तहसील में एक से अधिक उप निबंधक कार्यालय हैं वहां नया रोस्टर लागू कर दिया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसीलों में एक उपनिबंधक कार्यालय रविवार को भी खोला जाएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

रजिस्ट्रियों में आधार की अनिवार्यता के बाद सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। काफी समय से लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्री कार्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। रजिस्ट्री के लिए तमाम लोग दूसरे शहरों और राज्यों से भी आते हैं, रविवार को अवकाश के कारण रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहता है जिसके कारण अतिरिक्त अवकाश लेना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में भूमि क्रय की जा रही है जिनमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधि छह बजे के बाद ही उप निबंधक कार्यालय पहुंच पाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए पंजीकरण सेवाओं को सुभल और पारदर्शी बनाने के लिए समय में परिवर्तन किया गया है।

महानिरीक्षक की तरफ जारी शासनादेश के संदर्भ में लखनऊ के सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय रमेश कुमार का कहना है कि सदर तहसील में जहां पर पांच उपनिबंधक कार्यालय हैं वहां पर एक उप निबंधक कार्यालय एक बजे से रात आठ बजे तक खुलेगा। रजिस्ट्री के लिए आनलाइन अपाइंटमेंट एक बजे से सात बजे तक लिया जा सकेगा। शेष उपनिबंधक कार्यालयों में पहले की तरह ही दस बजे से पांच बजे कार्य होगा। इसी तरह सदर तहसील में ही किसी एक उपनिबंधक कार्यालय को रोस्टर के अनुसार रविवार को दस बजे से पांच बजे तक खोला जाएगा। जिस उप निबंधक कार्यालय को रविवार को खोला जाएगा और वहां पर अगले शनिवार को अवकाश रहेगा और माह का द्वितीय शनिवार होने की दशा में शुक्रवार को बंद रखा जाएगा। लखनऊ में सरोजनीनगर और मोहनलालगंज तहसील में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं इसलिए वहां पर भी यह शासनादेश लागू होगा। बख्शी का तालाब और मलिहाबाद तहसील में एक ही उपनिबंधक कार्यालय है वहां पर पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी।

## संक्षिप्त खबरें

### गुरुग्राम में 20 हजार के इनामी अंतरराज्यीय एटीएम लुटेरे मुजम्मिल गिरफ्तार, बदमाश पर 10 राज्यों में 10 केस दर्ज

**गुरुग्राम।** क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने एक इंटरस्टेट ATM लूट गैंग के एक सदस्य को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने उसे सेक्टर 45 इलाके से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूंह जिले के शिकारपुर गांव के रहने वाले मुजम्मिल (29) के रूप में हुई है। गुरुवार को पुलिस को पक्की सूचना मिली कि एक आरोपी अवैध हथियार के साथ इलाके में है। सूचना के आधार पर टीम ने उसे घेरकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सेक्टर 40 थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी मुजम्मिल ने ATM लूट गैंग का एक्टिव सदस्य होने की बात कबूल की। उसने बरामद हथियार नूंह इलाके के एक व्यक्ति से करीब 3,000 रुपये में खरीदा था। आरोपी इसे लूटपाट करने के इरादे से अपने पास रखे हुए था। राजस्थान में ATM बूथ पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमला और लूट की दो घटनाओं में उसके शामिल होने का पता चला है। इन मामलों में राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में हत्या, हत्या की कोशिश, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लूट, चोरी, सेंधमारी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों के करीब 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। इस दौरान उससे गैंग के दूसरे सदस्यों और घटनाओं के बारे में पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच जारी है।

### दिल्ली-फुलेरा के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

**पटौदी।** श्याम बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों और इलाके के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 20 से 23 फरवरी तक दिल्ली सराय रोहिल्ला-फुलेरा-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन नंबर 04401/04402 चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 20, 21 और 22 फरवरी को दिल्ली सराय रोहिल्ला से और 21, 22 और 23 फरवरी को फुलेरा जंक्शन से चलेगी। हर तरफ से तीन ट्रिप तय किए गए हैं। यह ट्रेन पूरी तरह से अनरिज़र्व्ड होगी और इसमें 17 कोच होंगे। यह दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, पटौदी रोड, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, रींगस जंक्शन और रेनवाल स्टेशनों पर रुकेगी। इससे इलाके के रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा। टाइमटेबल के अनुसार, ट्रेन नंबर 04401 शाम 7:10 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलेगी और 7:48 बजे गुरुग्राम, 8:20 बजे पटौदी रोड, 12:45 बजे रींगस और 2:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 04402 सुबह 11:40 बजे फुलेरा से चलेगी और 12:45 बजे रींगस, 4:08 बजे रेवाड़ी, 4:30 बजे पटौदी रोड, 5:00 बजे गुरुग्राम और 6:05 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसके अलावा, ट्रेन नंबर 09713/09714 भी 1 मार्च तक इसी टाइमटेबल के अनुसार चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। दैनिक रेल यात्री संघ पटौदी रोड के अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने इस सुविधा का स्वागत किया और रेलवे अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मांग की कि श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को रेगुलर चलाया जाए, ताकि इलाके के लोगों को हमेशा के लिए राहत मिल सके।

# भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति से की तौबा, कहा- झूठ बोलना पड़ता है

**● खेसारी लाल ने पिछले साल बिहार चुनाव से पहले अक्टूबर में राजनीति में कदम रखा और वह राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए. आरजेडी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार कहे जाने वाले सिंगर-एक्टर खेसारी लाल यादव अब राजनीति से तौबा करने जा रहे हैं. राजनीति में आने की अटकलों पर साफ जवाब देते हुए खेसारी लाल ने कहा कि वे महज एक कलाकार हैं और बस कलाकार ही रहना चाहते हैं।

खेसारी ने राजनीति रास नहीं आने की बात करते हुए कहा, 'राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, वहां झूठ बोलना पड़ता है और मैं सच बोलने वाला इंसान हूं. मैं कलाकार हूं, राजनीति नहीं करूंगा.' उनका कहना है कि वह हमेशा सच बोलने में यकीन रखते हैं. वह कलाकार हैं, और उन्हें उसी तरह देखा और पहचाना जाना चाहिए।

**पिछले साल राजनीति में आए**

**खेसारी लाल**

भोजपुरी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है. खेसारी लाल ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में राजनीति में कदम रखा और वह राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए. आरजेडी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सारण लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया।

हालांकि उनका चुनावी दांव काम कामयाब नहीं रहा. उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की छोटी कुमारी से 7,600 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा. पिछले 4 विधानसभा चुनावों 2010, 2015, 2020 और 2025 में बीजेपी को इस सीट से जीत मिलती रही है. बीजेपी के सीएन गुप्ता 2015 और 2020 में छपरा से विधायक चुने गए थे. हार के कुछ समय बाद ही खेसारी लाल ने हिंट दिया था कि वह जल्द ही राजनीति से दूरी बनाने वाले हैं.

**यहां सच बोलना मुश्किल: खेसारी लाल यादव**

पिछले महीने जनवरी में बिहार चुनाव में RJD और खुद की हार के कारणों पर खेसारी यादव ने कहा, मुझे लगता है कि हार का कारण सबको पता है. पूरा बिहार इसका कारण जानता है. तब उन्होंने राजनीतिक माहौल से निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें कलाकार बने रहने में ज्यादा आराम महसूस होता है।

खेसारी लाल ने राजनीति में अपने भविष्य को लेकर कहा था, 'मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के तौर पर ज्यादा अच्छा हूं. राजनीति हम जैसे लोगों के लिए सही नहीं है. यहां दिक्कत यही है कि सच बोलना मुश्किल हो जाता है. जो कोई भी सच बोलता है, वह राजनीति में ज्यादा आगे नहीं जा सकता.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर आपको झूठे वादे करना आता है, तो राजनीति में आ जाइए. अगर आप दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो राजनीति में आ जाइए।

## सरस मेले में बिहार से मखाने की शुद्धता का स्वाद, घरेलू मसालों और सत्तू की बढ़ी मांग

**गुरुग्राम।** ग्रामीण हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों के संगम बने सरस आजीविका मेले में इस बार बिहार के मखाने लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि मखानों को पूरी तरह पारंपरिक विधि से तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति लखपति दीदी गीता स्वयं कर रही हैं। गीता ने बताया कि तालाब में बीज डालने के लगभग छह माह बाद तैयार फसल को निकाला जाता है। इसके बाद बीजों को टोकरी में इकट्ठा कर धोया और धूप में सुखाया जाता है। अंतिम चरण में रेत के भीतर लकड़ी से पीटकर मखाने तैयार किए जाते हैं। शुद्धता और देसी तरीके से निर्माण के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। लोग न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए भी मखाने खरीद रहे हैं। लेजर वैली ग्राउंड में लगे इस मेले में देशभर से आए स्वयं सहायता समूहों ने अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। बिहार पवेलियन में मखानों के साथ-साथ स्टाल पर मसाले, चना का सत्तू, धनिया पाउडर, अदौरी पाउडर और मखाना पाउडर भी उपलब्ध हैं।

# दिल्ली के नांगलोई सर्विस रोड पर दुकानदारों का कब्जा,जाम की समस्या उत्पन्न

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**
**बादल हुसैन**

**दिल्ली** के रोहतक रोड नांगलोई सर्विस रोड पर अतिक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है। यहां पर काफी संख्या में दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर समान रख कर घेर लिया है। सर्विस रोड मार्केट में तब्दील हो गया जिसके कारण राहगीरों और दुकानदारों के बिच नोक झोंक देखने को रोज मीलती है। वहीं इस तरह से अतिक्रमण जाम की समस्या भी बना रही है। सुत्रो ने बताया कि ऐ सब प्रशासन के मीलि भगत के कारण दुकानदारों का हौसला बुलंद हैं। नांगलोई फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर दुकानदारों ने इस तरह रोड को कब्ज कर रखा है जिसके चलते आवा गमन मे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि दुकानदारों ने दुकान की पुरी छज्जा रोड पर निकाल रखा है। और बड़े बड़े डिस्प्ले लगाकर रोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन देखता रह गया।

# स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में सख्त डीएम, लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश

**● आरआरसी व नालों की टैपिंग में लापरवाही पर डीएम शैलेष कुमार सख्त, जारी किए नोटिस**

**भदोही में स्वच्छ भारत मिशन की गहन समीक्षा, लापरवाही पर अधिकारियों पर गिरी गाज**

**स्वच्छता मिशन की बैठक में डीएम का सख्त रुख, आरआरसी संचालन व शौचालय प्रगति पर विशेष जोर**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**भदोही–** जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मैनेजमेंट कमेटी के कार्यक्रम की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आरआरसी निर्माण एवं संचालन की स्थिति, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत चिन्हित नालों की टैपिंग की स्थिति बेहद खराब होने व कार्य में लापरवाही बरतने पर डीपीआरओ संजय कुमार मिश्र, स्वच्छ भारत मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ.सरोज पांडेय को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिया। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड औराई में गंगा के किनारे चिन्हित नालों की प्रगति कार्य न होने पर व कार्य में लापरवाही बरतने पर एडीओ पंचायत औराई धीरेन्द्र यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिया। साथ ही साथ सभी अन्त्येष्टि स्थल के कार्यो की गुणवत्ता जॉच कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को दिया।

समीक्षा में स्वच्छता ही सेवा 2025 प्रगति पर विचार, ग्रामों में आर आर सी निर्माण की स्थिति, आर आर संचालन की स्थिति, मॉडल ग्राम के विभिन्न स्तरों की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत शौचालय की प्रगति का विवरण, जनपद के ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय में नियुक्त केयरटेकर की स्थिति आदि की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के सभी अभियानों, कार्यक्रमों को समय सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत शौचालय हेतु जो पात्र व्यक्ति छुटे हैं उनका ऑनलाइन आवेदन करा कर ग्राम प्रधान से सर्टिफिकेट ले लें कि, इसके अलावा अब कोई पात्र व्यक्ति ग्राम में नहीं छूटा हैं। जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में आरआरसी का संचालन जल्द ही सुनिश्चित हो।जिन ग्राम पंचायत में आरआरसी केंद्र बन गया है, उन ग्राम पंचायत में क्वालिटी के साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराए कूड़ा का सेग्रीगेशन भी करने का निर्देश संबंधित ग्राम पंचायत के अधिकारियों को दिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु व्यक्तिगत शौचालय की प्रगति का विवरण लक्ष्य के क्रम में 7260, व डीडीडब्ल्यूएस बेवसाइट पर ऑनलाईन पेन्डिंग प्रार्थना पत्रों की संख्या 7982, विकास खण्डों से प्राप्त सत्यापन पात्र लाभार्थियों की संख्या 4364, विकास खण्डों से अवशेष सत्यापन पात्र लाभार्थियों की संख्या 2896 है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के क्रियाशीलता की स्थिति में विकास खण्डों में स्थित ग्राम पंचातयों की कुल संख्या 546, क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों के ग्राम पंचायतों की संख्या 540, क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों के ग्राम पंचायतों का 99.72 प्रतिशत, अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों के ग्राम पंचायतों की संख्या 06 अवशेष है। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर शत-प्रतिशत शौचालय क्रियाशील कराने का निर्देश दिया। बैठक में शौचालयों के प्रगति, चयनित मॉडल गॉव, शौचालयों के रेट्रोफिटिंग के प्रगति बिन्दुओं पर बल दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ.सरोज पांडेय, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

# दिल्ली में कर्ज चुकाने के लिए भांजे ने की मौसी की निर्मम हत्या, दोस्त भी गिरफ्तार

**● भांजे उमेश ने कर्ज चुकाने को मौसी की हत्या की।**

**● लूटपाट के दौरान चाकू मारकर की गई थी हत्या।**

**● पुलिस ने भांजे उमेश और दोस्त विपिन को दबोचा।**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**पूर्वी दिल्ली।** ज्योति नगर इलाके में घर में घुसकर लूट के लिए की गई अधेड़ महिला की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महिला के भांजे व इसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पांच लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए रुपये न होने पर युवक ने अपनी मौसी की हत्या की थी। आरोपित की पहचान महिला के भांजे उमेश व इसके दोस्त विपिन के रूप में हुई है। इनके पास से लूटे गए सोने के गहने, वारदात में इस्तेमाल बाइक और चाकू बरामद किया है। दोनों इवेंट मैनेजमेंट में थे।

विमला देवी परिवार के साथ अमर कालोनी में रहती थी। परिवार में पति महावीर व दो शादीशुदा बेटे हैं। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। कुछ दिनों पहले महावीर उत्तर प्रदेश के कासगंज में किसी काम से गए हुए थे। उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। पुलिस ने बताया कि 15 फरवरी की दोपहर को पड़ोसियों ने सूचना दी कि एक घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। घर के बाहर का दरवाजा खुला हुआ था।

महिला के दोनों हाथ, गला व शरीर के कई हिस्सों पर चाकू के निशान थे। शव बेड पर पड़ा हुआ था। घर में महिला के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में एएसआइ नरेश मंगल, हेड कांस्टेबल अनुज, राहुल की टीम बनाई। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर आरोपितों की पहचान की। टेक्निकल सर्विलांस के जरिये दोनों आरोपितों को नंद नगरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।

**फाइनेंसर से लिया हुआ था लोन, कारोबार में हो रहा था घाटा**

आरोपित उमेश ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। उसने एक फाइनेंसर से पांच लाख रुपये का लोन लिया हुआ था। उसे कारोबार में घाटा हो रहा था। वह लोन चुका नहीं पा रहा था। घर वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे थे। तब उसने अपने दोस्त के साथ मौसी से लूट की योजना बनाई।

उसे पता था किस दिन उसके मौसा उत्तर प्रदेश जाएंगे। जब वह वारदात करने दोस्त के साथ गया तो पता नहीं था कि रकम व गहने घर में कहा रखे हैं। मौसी ने अंगूठी व कान की बालियां पहनी हुई थी। वह मौसी से लूटपाट करने लगा। विरोध करने पर चाकू से वार करके हत्या कर दी।

# कैंपस इंटरव्यू में 12 एमबीए छात्रों को मिली नौकरी

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**श्रीभूमि:** असम विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग के 12 एमबीए छात्रों ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्हें देश की अग्रणी टीएमटी बार निर्माता कंपनियों में से एक, श्याम स्टील इंडस्ट्रीज में कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी के अवसर मिले हैं। बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित चयन प्रक्रिया के जरिए इनका चयन किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में कंपनी का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। इस बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया। अंततः 12 एमबीए छात्रों को कंपनी के विभिन्न जिम्मेदार पदों के लिए चुना गया। इस अवसर पर कंपनी की ओर से जनरल मैनेजर सायन घोष, रीजनल मैनेजर हिमनीश बोराह और एरिया मैनेजर दीपांकर वैद्य उपस्थित थे। चयनित छात्र हैं: रोजी देब, भाग्यश्री दास, राजज्योति देब, सायन राय, स्नेहा रानी दास, कुमारजीत राय, रोहन देब, संघमित्रा दास, श्रेयता दत्त, भावोसे गुरुंग, अमन कुमार दे और रोनाक दास। इस कैंपस प्लेसमेंट अभियान का नेतृत्व विभागाध्यक्ष और करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रोफेसर देबमाल्य घोष ने किया। उन्हें भर्ती सलाहकार रश्मि दास और समन्वयक सौरव बनिक ने सहयोग प्रदान किया।इस बीच, कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत ने चयनित छात्रों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि छात्रों की यह सफलता पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि हमारे छात्र राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संस्थानों में अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत संबंध स्थापित होने से छात्रों के लिए रोजगार के अवसर और अधिक विस्तृत होंगे।

# द्वारका हादसा: 'नाबालिग आरोपी को पछतावा नहीं', JJB ने अंतरिम जमानत सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

**● जेजेबी ने नाबालिग के पश्चाताप न होने पर चिंता जताई**

**● आरोपित को बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंतरिम जमानत मिली**

**● न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**पश्चिमी दिल्ली।** द्वारका हादसे के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने हादसे के आरोपित नाबालिग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कई टिप्पणियां की थी। बोर्ड ने अपनी जांच में पाया था कि आरोपित नाबालिग को किसी व्यक्ति के जीवन की कीमत का पूर्ण रूप से बोध नहीं है और न ही किशोर से पूछताछ के बाद यह प्रतीत होता है कि अपने उस कृत्य को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है।

**बोर्ड ने किशोर के व्यवहार पर जताई चिंता**

बोर्ड ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित किशोर के व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए आरोपित को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम राहत प्रदान की थी। इस फैसले के बाद ही पीड़ित परिवार, विशेषकर साहिल की मां की न्याय की गुहार और तेज हो गई है।

**9 मार्च तक के लिए है अंतरिम जमानत**

सुनवाई के दौरान आरोपित के पक्ष ने दलील दी थी कि यह घटना केवल एक हादसा थी। आरोपित का दावा किया था कि यह घटना शुद्ध रूप से आकस्मिक थी और किसी को चोट पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं था। बचाव पक्ष की याचिका में कहा गया कि आरोपित ने स्वयं पुलिस को सूचित किया और शुरुआत से ही जांच में पूर्ण सहयोग दिया।

तमाम दलीलों और टिप्पणियों के बीच, बोर्ड ने आरोपित की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए उसे 10 फरवरी को राहत दी थी। इसमें आरोपित को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और पेपर के मद्देनजर 9 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई। इसमें आरोपित को 10 हजार के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर छोड़ा गया है। इस दौरान वह अपने पिता की कस्टडी में रहेगा। बोर्ड ने अपने आदेश में साफ किया है कि यह राहत अंतरिम है और इसे मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई बाद में होगी।

# ग्रेटर नोएडा के किसानों की बल्ले-बल्ले, जमीन की कीमतें बढ़ीं; किसानों को मिलेगी बढ़ी हुई रकम

**» ग्रेटर नोएडा में किसानों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ भूमि मुआवजा।**

**» अथॉरिटी की आगामी बैठक में दरों में वृद्धि का प्रस्ताव आएगा।**

**» वर्तमान 4200/वर्ग मीटर दर से किसान असंतुष्ट, बढ़ोतरी की मांग।**

**ग्रेटर नोएडा।** ग्रेटर नोएडा के किसानों को जल्द ही बढ़े हुए मुआवज़े की दरों का तोहफ़ा मिल सकता है। अथॉरिटी की आने वाली मीटिंग में इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की उम्मीद है। अथॉरिटी किसानों से सहमति के आधार पर ज़मीन खरीदती है। बदले में उन्हें एक तय मुआवजा दिया जाता है। अभी लगभग 4,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवज़ा दिया जाता है, जबकि येइदा में मुआवज़े की दर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई है। ग्रेटर नोएडा के किसान भी मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मुआवजे की दर में 10 परसेंट की बढ़ोतरी की गई थी। अथॉरिटी ने मौजूदा मुआवजे की दर और मार्केट रेट की स्टडी की है। सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है।

# गलगोटिया रोबोट डॉग विवाद: समाजवादी पार्टी छात्र यूनियन ने किया प्रोटेस्ट, यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग

**» समाजवादी छात्र सभा ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया।**

**» रोबोटिक डॉग विवाद से देश की बदनामी का आरोप लगाया।**

**» यूनिवर्सिटी ने गलती मानी, फैकल्टी पर कार्रवाई का भरोसा दिया।**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** दिल्ली AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिखाए गए रोबोटिक डॉग की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हुई शर्मिंदगी का मामला अब पॉलिटिकल तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट यूनियन, गौतम बुद्ध नगर के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हालांकि, पुलिस से भरोसा मिलने के बाद उन्होंने मेमोरेंडम देकर प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। यूनियन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित नागर की लीडरशिप में पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट किया और एक्शन की मांग की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित नागर और स्टेट प्रेसिडेंट प्रशांत भाटी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ऐसी हरकतें देश के साथ बेइज्जती और धोखा है। उन्होंने मांग की कि यूनिवर्सिटी की मान्यता तुरंत कैंसिल की जाए, केस फाइल किया जाए और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए। यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए।

**मैनेजमेंट ने मान ली अपनी गलती**

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एनके गौड़ ने कहा कि मैनेजमेंट ने अपनी गलती मान ली है।

उन्होंने कहा, 'हम एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी हैं। हम कभी नहीं चाहते कि देश की इज्जत कम हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। हां, हमारी फैकल्टी से गलती हुई, उनके शब्दों का चुनाव गलत था। 'हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और कार्रवाई चल रही है। प्रोफेसर नेहा को अभी हटाया नहीं गया है। उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है।